एक ऐसा बजट जो स्थिरता के साथ विकास को बढ़ावा देता है

द हिन्दू

पेपर- III (अर्थव्यवस्था)

23 जुलाई को पेश किया जाने वाला 2024-25 का अंतिम बजट नई सरकार का पहला बजट होगा। यह सरकार के लिए अपनी नीति प्राथमिकताओं के साथ-साथ मध्यम अवधि के विकास और रोजगार के परिप्रेक्ष्य को प्रदान करने का अवसर है। जारी वैश्विक आर्थिक मंदी को देखते हुए, भारत को बड़े पैमाने पर घरेलू विकास चालकों पर निर्भर रहना होगा। अल्पकालिक उद्देश्य न्यूनतम 7% की वृद्धि सुनिश्चित करना हो सकता है, जबकि मध्यम अवधि का उद्देश्य वास्तविक जीडीपी विकास दर को 7%-7.5% की सीमा में बनाए रखना हो सकता है। अगले तीन से चार वर्षों में जीडीपी के सापेक्ष राजकोषीय घाटे को मौजूदा स्तरों से राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) के 3% के सुसंगत स्तर तक कम करके इसे सुगम बनाया जाएगा। उत्पादन की संरचना में अपेक्षाकृत अधिक श्रम-गहन क्षेत्रों पर अतिरिक्त जोर देने को छोड़कर रोजगार उद्देश्य विकास उद्देश्य से स्वतंत्र नहीं है।

निवेश और बचत की संभावनाएं

निरंतर आधार पर 7% से अधिक की वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए, हमें 35% की वास्तविक निवेश दर की आवश्यकता है। 2023-24 के लिए नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सकल स्थिर पूंजी निर्माण (GFCF) के रूप में मापी गई वास्तविक निवेश दर 2022-23 के लिए 33.3 और 2023-24 के लिए 33.5 थी। हालांकि सकल पूंजी निर्माण (GCF) मामूली रूप से अधिक है, लेकिन हमें 7% से अधिक की वृद्धि को बनाए रखने के लिए मध्यम अवधि में GFCF का स्तर 35% या उसके आसपास सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, यह मानते हुए कि वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात पाँच है। 2022-23 में नाममात्र और वास्तविक शर्तों में बचत का जीडीपी अनुपात क्रमशः 30.2% और 32.8% था। चिंता का एक बिंदु घरेलू क्षेत्र की वित्तीय बचत में हाल ही में आई गिरावट है, जो 2022-23 के लिए उपलब्ध जानकारी के अनुसार सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय का 5.2% तक गिर गई है। चूंकि यह विदेशी पूंजी के प्रवाह के अलावा निवेश योग्य अधिशेष प्रदान करता है, इसलिए निजी क्षेत्र के लिए उचित दरों पर निवेश योग्य अधिशेष तक पहुंच की सुविधा के लिए घरेलू वित्तीय बचत दर को बढ़ाना महत्वपूर्ण है।

मांग पक्ष पर, निर्यात की कम संभावनाओं के कारण हाल के वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में शुद्ध निर्यात का योगदान नकारात्मक या कम रहा है। यह 2022-23 में 0.5% अंक और 2023-24 में (-)2.0% अंक पर था। भारतीय सेवा निर्यात के माल निर्यात की तुलना में बेहतर प्रदर्शन जारी रखने की उम्मीद है, जो 2023-24 में सिकुड़ गया। जब तक निर्यात मांग में तेजी नहीं आती और निजी निवेश में तेजी नहीं आती, तब तक भारत को विकास को समर्थन प्रदान करने के लिए सरकारी निवेश मांग पर निर्भर रहना होगा।

बजटीय विकल्पः

अंतरिम बजट की तुलना में, उच्च कर और गैर-कर राजस्व दोनों के कारण केंद्र की राजस्व स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है। महालेखा नियंत्रक (CGA) के वास्तविक आंकड़ों के अनुसार, 2023-24 के लिए सकल कर राजस्व (GTR) का आधार संख्या 34.65 लाख करोड़ रुपये है, जो अंतरिम बजट के संशोधित अनुमानों (RE) से 27,581 करोड़ रुपये अधिक है। हमें उम्मीद है कि 2024-25 के लिए नाममात्र GDP वृद्धि कम से कम 11% होगी, जो 7% वास्तविक वृद्धि और 3.8% निहित मूल्य अपस्फीति (IPD)-आधारित मुद्रास्फीति से बनी होगी। 2023-24 के 1.3% के स्तर की तुलना में IPD-आधारित मुद्रास्फीति में वृद्धि अपेक्षित उच्च थोक मूल्य सूचकांक (WPI) मुद्रास्फीति के कारण है जो 2023-24 में (-)0.7% थी। 1.1 की उछाल और 12.1% की जीटीआर वृद्धि के साथ, हम 38.8 लाख करोड़ रुपये की जीटीआर परिमाण की उम्मीद करते हैं। केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी के बाद केंद्र के लिए शुद्ध कर राजस्व 26.4 लाख करोड़ रुपये होगा, जो अंतरिम बजट में प्रदान किए गए 26 लाख करोड़ रुपये से थोड़ा अधिक है।

अंतरिम बजट अनुमानों की तुलना में गैर-कर राजस्व भी अधिक रहने की उम्मीद है, जिसका मुख्य कारण भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा 2.11 लाख करोड़ रुपये का संवर्धित लाभांश है। हमें उम्मीद है कि केंद्र का गैर-कर राजस्व 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक होगा। यह ध्यान देने योग्य है कि RBI से कोई भी हस्तांतरण विस्तारकारी होने वाला है क्योंकि इसका तरलता प्रभाव होगा। यह हस्तांतरण RBI द्वारा सरकार को ऋण के रूप में माने बिना ऋण के विस्तार के समान है। इस प्रकार, इसका मौद्रिक नीति पर प्रभाव पड़ता है। हालांकि, केंद्र सरकार की बेहतर राजस्व स्थिति सरकार के राजकोषीय समेकन लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगी।

यह मानते हुए कि सरकार अंतरिम बजट में घोषित 5.1% राजकोषीय घाटे के जीडीपी अनुपात का पालन करती है, कुछ गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों को ध्यान में रखने के बाद कुल व्यय जिसे वित्तपोषित किया जा सकता है, वह 49 लाख करोड़ रुपये है। इसे राजस्व और पूंजीगत व्यय के बीच आवंटित करना होगा। अंतरिम बजट व्यय परिमाणों के साथ, 2024-25 में राजस्व व्यय वृद्धि 2023-24 के लिए सीजीए वास्तविक से 4.6% अधिक हो जाती है। बढ़ी हुई सब्सिडी, बढ़े हुए स्वास्थ्य व्यय और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के लिए बढ़े हुए आवंटन के कारण उच्च राजस्व व्यय को समायोजित करने के लिए इस वृद्धि को बढ़ाना पड़ सकता है ताकि ग्रामीण आबादी को बड़े पैमाने पर सहायता और राहत प्रदान की जा सके।

चालू वर्ष में सामान्य मानसून रहने की उम्मीद के साथ ग्रामीण आय में कुछ सुधार की उम्मीद है। हमारे अनुमानों से संकेत मिलता है कि भले ही राजस्व व्यय वृद्धि को 8% तक बढ़ाया जाता है, इससे 2023-24 के वास्तविक आंकड़ों की तुलना में 3 लाख करोड़ रुपये के करीब अतिरिक्त राजस्व व्यय उपलब्ध होगा। इससे 2024-25 में पूंजीगत व्यय में 19.2% की वृद्धि के लिए राजकोषीय गुंजाइश बनी रहेगी, जो निवेश मांग का समर्थन करने के लिए आवश्यक होगी, जिसके परिणामस्वरूप बुनियादी ढांचे का विस्तार होगा जो सरकार के मध्यम अवधि के उद्देश्यों के अनुरूप है। कुछ कर युक्तिकरण उपाय किए जा सकते हैं, जब तक कि वे कोई महत्वपूर्ण राजस्व बलिदान नहीं दर्शाते हैं। चल रही उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के कुछ विस्तार पर विचार किया जा सकता है, खासकर अगर यह रोजगार सृजन का समर्थन करता है।

एफआरबीएम लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता

निष्कर्ष रूप में, बजट को विकास को स्थिरता के साथ जोड़ने का लक्ष्य रखना चाहिए। स्थिरता में मूल्य स्थिरता और राजकोषीय स्थिरता दोनों शामिल हैं। अल्पावधि से मध्यम अवधि में FRBM लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता का संकेत देना महत्वपूर्ण है। यदि 2024-25 में राजकोषीय घाटे को जीडीपी अनुपात में 5.1% तक लाया जाता है, तो इसे जीडीपी के 3% तक लाने में तीन से चार साल और लग सकते हैं। जैसे-जैसे राजकोषीय घाटे को जीडीपी अनुपात में कम किया जाता है और नाममात्र जीडीपी वृद्धि को 11%-11.5% की सीमा में रखा जाता है, ऋण जीडीपी अनुपात और राजस्व प्राप्तियों के लिए ब्याज भुगतान अनुपात भी कम हो जाएगा, जिससे राजकोषीय घाटे में कमी आएगी, जिससे एक पुण्य चक्र का निर्माण होगा।

प्रारंभिक परीक्षा के संभावित प्रश्न (Prelims Expected Question)

प्रश्न : निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. नई सरकार का पहला बजट 23 जुलाई को पेश किया जाएगा।
2. अंतरिम बजट 2024-25 में घोषित राजकोषीय घाटा 5.1% था।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

Que. Consider the following statements-

1. The first budget of the new government will be presented on 23 July.
2. The fiscal deficit announced in the interim budget 2024-25 was 5.1%.

Which of the statements given above is/are correct?

(a) Only 1 (b) Only 2
(c) Both 1 & 2 (d) Neither 1 nor 2

उत्तर :

मुख्य परीक्षा के संभावित प्रश्न व प्रारूप (Mains Expected Question & Format)

प्रश्न: भारतीय अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आगामी केंद्रीय बजट में आपके अनुसार क्या कदम लिए जाने चाहिए?

उत्तर का दृष्टिकोण :

- उत्तर पहले भाग में भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति की संक्षिप्त चर्चा कीजिए।
- दूसरे भाग में आगामी केंद्रीय बजट के लिए अपने सुझावों का वर्णन कीजिए।
- अंत में आगे की राह दिखाते हुए निष्कर्ष दें।

नोट : अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।